राष्ट्रीय वस्त्र निगम की विभिन्न मिलों द्वारा बेची गई अतिरिक्त भूमि

40. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की विभिन्न मिलों द्वारा बेची गई कुल अतिरिक्त भूमि का मिलवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि की बिक्री के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) इससे कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी किसी भी बेशी भूमि को नहीं बेचा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Funds to upgrade Garments and Textile Industry Technology

41. DR. JAGANNATH MISHRA; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have received any demand from the representatives of Garment and Textile Industry for a fund of Rs. 2000 crores to upgrade its technology and improve competitiveness in the global market;

(b) if so. the details there of; and

(c) the reaction of Government in regard thereto?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) Government have not received any specific demand from the representatives of Garments and Textile industry for a fund of Rs. 2000 crores to upgrade its technology and improve competitiveness in the global market.

(b) and (c) Do not arise.

Road Safety improvement in West Godavari District in Andhra Pradesh

42. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state;

(a) whether any report has been called from Roads and Building Department of Andhra Pradesh on the road safety improvements, to be made in West Godavari district;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps proposed to involve the public in improving road safety on National Highway No. 5 in West Godavari district; and

(d) the schedule of action recommended?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) Yes, Sir. Chief Engineer (National Highways) Andhra Pradesh has been requested to furnish his views regarding the Road Safety situation on NH. 5 in West Godavari Distt, of Andhra Pradesh, detailing the deficiencies, if any, as also the possible remedial measures. Reply from the State Govt, is awaited.

(c) and (d) Does not arise.

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गुजरात के लिए स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

43. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा सर्वेक्षण की गई और केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की गई नई सिंचाई परियोजनाओं संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से गुजरात के पंच महल के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित शेष परियोजनाओं के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र): (क) स्वीकृति के लिए लंबित गुजरात की नई-वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) स्वीकृति के लिए लंबित गुजरात की परियोजनाओं में से गोमा सिंचाई परियोजना से गुजरात में पंचमहल के आदिवासी क्षेत्रों को लाभ होगा।

(ग) गोमा सिंचाई परियोजना पर, राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है और पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

(घ) यद्यपि परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय-सीमा है, तथापि स्वीकृति में देरी विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने में राज्य सरकारों द्वारा हुए विलंब के कारण हुई । इसलिए अन्तिम निर्णय के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

स्वीकृति के लिए लंबित गुजरात की नई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लाभ हेक्टे. में	स्वीकृति की स्थिति
वृहद परियोजनाएं					
1.	मच्छू-1 सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	फरवरी, 91	11.12	2,140	8.12 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को परामर्शदात्री समिति द्वारा 8/93 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के अधीन तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार की टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।
मध्यम परियोजनाएं					
2.	वालान सिंचाई परियोजना	मई, 90	22.16	7,390	परामर्शदात्री समिति द्वारा 3/91 में इस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन दृष्टि से, कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी और उसे फसल स्वरूप की पुनरीक्षा करनी थी। इस

क्रम सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लाभ हेक्टे में	स्वीकृति की स्थिति
					परियोजना को कल्याण मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1994 में पुनर्वास और पुनर्स्थापना दृष्टि से स्वीकृति कर दिया गया। राज्य सरकार ने वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा फसल स्वरूप की पुनरीक्षा भी करनी है।
3.	उन्द-II	दिसम्बर, 91	38.94	4,250	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है।
4.	गोमा	मई, 94	31.10	7,000	-वही-
5.	ओजत-II	अक्तूबर, 93	59.73	7,970	-वही-
6.	मिट्टी सिंचाई का पुनरूद्धार	जून, 93	14.51	2,030	-वही-
7.	महिपादा जल संसाधन परियोजना	सितम्बर, 93	25.74	2,340	-वही-
8.	चारत्-II सिंचाई	दिसम्बर, 91	30.38	6,150	-वही-
9.	नानोबारसन	नवम्बर, 91	32.40	3,760	-वही-
10.	बकरोल	जनवरी, 95	23.86	4,290	-वही-

Transportation to North-East Region Through Bangladesh

44. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any initiative to facilitate transportation through Bangladesh to connect N.E. States to the mainland of India:

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is any positive response from the Government of Bangladesh; and

(d) the steps Government propose to materialise this long-standing demand?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL) : (a) to (d) The question of transit facilities through Bangladesh to provide transportation link between the North-eastern States of India and the mainland has been raised on many occasions with the Government of Bangladesh. The subject remains under discussion between the two Governments.

Indo-Russian Defence Agreement

45. SHRI BHAGABAN MAJHI:
SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:"

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state: